झारखण्ड सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिति
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

सरकारी अस्पतालों में दी जानेवाली सेवाओं की ब्रांडिंग करनी होगी : *अभियान निर्देशक, एनएचएम*

रांची, 28 जून 2018: बृहस्पतिवार को नामकुम स्थित आईपीएच सभागार में 'ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसियल्स ऑन स्ट्रेंथेन एसपिरेशनल एंड मॉडर्न हेल्थ डिस्ट्रिक्ट्स' विषय पर एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरूआत करते हुए अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कृपानंद झा ने कहा कि हमारे राज्य में 73 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आकांक्षी जिले हैं। इसमें दी जानेवाली सेवाओं की ब्रांडिंग करनी होगी। इस संबंध में सभी जिलों को चिट्ठी भेजी जा रही है।

जिला अस्पताल पर उच्च स्तरी सुविधा देनी होगी

अभियान निदेशक श्री झा ने कहा कि जिला अस्पताल पर उच्च स्तरी सुविधा देनी होगी ताकि जो लोग बाहर इलाज करवाने जा रहे हैं वो जिला अस्पताल और अन्य केंद्रों पर इलाज के लिए आयें। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चुने गये हैं जहां ओरल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और अन्य सुविधायें दी जायेंगी। उन्होंने कहा कि विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान में निर्धारित समय पर डाटा इंट्री का काम पूरा किया जाये। ऐसा देखा जा रहा है कि मिशन इंद्रधनुष में हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं। इसे सुधार करने की जरूरत है। श्री झा ने कहा कि केंद्र या राज्य सरकार के जो दिशानिर्देश जारी किये गये हैं उसी दायरे में रहकर काम करना होगा।

जिलों को एक्शन प्लान बनाने का निर्देश

कार्यक्रम के दौरान अभियान निदेशक ने स्वास्थ्य मानकों में सुधार के लिए जिलों से आये सिविल सर्जन और अन्य अधिकारियों को एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में 19 अकांक्षी जिले हैं जिनकी समीक्षा 31 से 32 इंडीकेटर्स के प्रदर्शन आधार पर की जायेगी। उन्होंने कहा कि इसमें से 50 प्रतिशत इंडिकेटर्स पहले से चल रहे कार्यक्रमों से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि आईईसी मेटेरियल, दवाईयां ब्लॉक से नीचले स्तर तक कैसे पहुंचे इसका पैमाना तय करना होगा। मासिक और तिमाही स्तर पर यह देखना होगा कि कितने सामग्री ब्लॉक और उससे नीचे पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान आयुष्मान भारत कार्यक्रम की भी चर्चा की।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान से चिकित्सकों को जोड़ने का निर्देश

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में अभी तक 114 चिकित्सक इनरॉल हो सके हैं। इस संख्या को बढ़ाने के लिए प्राइवेट चिकित्सकों के साथ बैठक आयोजित करें। उन्हें सेवा देने संबंधी पूरी जानकारी दें और आस पास के क्षेत्रों में इस दिन उन्हें ड्युटी दें। इस अभियान में रिटायर्ड चिकित्सकों को भी जोड़ें।

जिला अस्पतालों में भ्रमण जरूरी : डॉ हिमांशु भूषण

अधिकारियों को संबोधित करते हुए पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एनएचएसआरसी के सलाहकार और प्रमुख डॉ हिमांशु भूषण ने स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार मानकों के कई आयामों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिला अस्पतालों में नियुक्त अस्पताल प्रबंधक अस्पताल में लगाकार भ्रमण करें तो 70 प्रतिशत तक समस्यायें ठीक हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए दूसरे जिलों के तैयार प्रोटोकॉल की मदद ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि जब से एनएचएम शुरू हुआ है कई पदों पर लोग नहीं मिले हैं और कई पदों पर नियुक्त किये गये लोग त्यागपत्र दे चुके हैं। ऐसे जिलों में नियुक्ति के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में डाटा का पुर्ननिरीक्षण जरूरी है और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए अन्य विभागों का सहयोग लिया जा सकता है। उन्होंने मातृत्व स्वास्थ्य से संबंधित दिये गये रोडमैप पर भी चर्चा की। डॉ भूषण ने नीति आयोग के इंडिकेट्र्स पर भी चर्चा की।

डाटा की जांच करेगी नीति आयोग की टीम

डॉ हिमांशु भूषण ने कहा कि एचएमआईएस में जो आंकड़े डाले जा रहे हैं उसे नीति आयोग की टीम जांचेगी। इसके लिए आयोग हर तीन महीने में टीम भेजेगी। ये टीम एचएमआईएस डाटा को फिल्ड में जाकर सत्यापित करेगी। डॉ भूषण ने जिलों से आये सिविल सर्जनों को मासिक बैठक में इंडिकेटर्स पर चर्चा करने का निर्देश दिया। इनफ्रास्ट्रक्चर और क्लिनिकल सर्विस पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हर सरकारी अस्पताल में एक हाई डिपिडेंसी युनिट बनायी जानी चाहिए ताकि इलाज के लिए आ रहे मरीजों के परिजनों पर निजी अस्पतालों के खर्च का बोझ नहीं पड़े।

इस कार्यक्रम में अजीत कुमार, डॉ नबोजीत रॉय, डॉ अजीत प्रसाद, डॉ दीपावली, डॉ वीणा सिन्हा, डॉ पुष्पा मारिया बेक, डॉ एलआर पाठक, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, अकई मिंज, सुचंद्रा पांडा, नीता कुजूर जिलों के सिविल सर्जन और राज्य परामर्शी उपस्थित थे।

नोडल ऑफिसर
आई0 ई0 सी0 कोषांग